विदेशी निवेश अथवा विदेशी पूंजी से अर्थ

विदेशी निवेश से अर्थ किसी उद्योग में विदेशी सरकार, संस्था या समुदाय द्वारा पूंजी के लगाये जाने से है। यह पूंजी विदेशी मुद्रा, विदेशी मशीनों व विदेशी तकनीकी ज्ञान के आधार पर लगायी जा सकती है जिसका स्वरूप पूंजी में हिस्सा बँटाना (Capital Participation), विदेशी सहयोग (Foreign Collaboration) व विदेशी मुद्रा में ऋण (Loans in Foreign Currency), आदि हो सकता है, लेकिन कुछ विदेशी संस्थाएँ या सरकारें ऋणों के साथ-साथ कुछ अनुदान (Grant) भी देती हैं जिसको वे वापस नहीं लेती हैं। यह अनुदान विदेशी सहायता (Foreign Assistance) कहलाता है। यह सहायता वर्गीकृत व अवर्गीकृत (Project aid and non-project aid) दोनों प्रकार की होती है। वर्गीकृत सहायता किसी विशेष परियोजना के लिए होती है उसको उसी परियोजना पर व्यय करना पड़ता है, जबकि अवर्गीकृत सहायता किसी भी परियोजना के लिए काम में लायी जा सकती है।

आजकल 'विदेशी निवेश' के स्थान पर 'विदेशी सहायता' शब्द अधिक प्रचलित है। अतः इसका अर्थ भी अधिक व्यापक हो गया है। वर्तमान में **विदेशी सहायता शब्द में विदेशी पूंजी, विदेशी ऋण, विदेशी अनुदान, आदि सभी शामिल हैं।**

विदेशी निवेश के प्रकार
(TYPES OF FOREIGN INVESTMENT)

विदेशी निवेश तीन प्रकार के होते हैं—(1) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, (2) एक सरकार से दूसरी सरकार को ऋण, (3) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा ऋण।

(1) **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** (Direct Foreign Investment)—यह विनियोग एक देश की निजी विदेशी संस्थाओं द्वारा दूसरे देश की निजी या सार्वजनिक संस्थाओं में किया जाता है। इस विनियोग का दूसरा नाम विदेशी उद्यमी विनियोग भी है। प्रत्यक्ष निजी विदेशी विनियोग दो प्रकार का होता है : (i) प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग व (ii) पोर्टफोलियो विनियोग (Portfolio Investment)। **प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग में विदेशी पूंजीपतियों का कम्पनियों पर स्वामित्व के साथ-साथ प्रबन्धकीय नियन्त्रण भी रहता है।** इसके विपरीत, **पोर्टफोलियो स्वामित्व में प्रभुत्व एवं नियन्त्रण विदेशी पूंजीपतियों का नहीं रहता है, बल्कि प्रभुत्व एवं नियन्त्रण उस देश पर ही छोड़ देते हैं जिस देश में कम्पनी स्थापित हुई है।** इस प्रकार के विनियोग पर केवल ब्याज या निश्चित लाभांश की गारण्टी होती है। इस प्रकार ऐसे विनियोग में विनियोगकर्ता अपने ऊपर जोखिम नहीं लेते हैं और न प्रबन्ध पर ही नियन्त्रण रखते हैं।

(2) **एक सरकार से दूसरी सरकार को ऋण**—विदेशी पूंजी लगाने का यह दूसरा तरीका है जिसमें एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार को ऋण प्रदान करती है। यह ऋण दो प्रकार के होते हैं : (i) उदार ऋण (Soft Loans) व (ii) अनुदार ऋण (Hard Loans)। **उदार ऋण वे होते हैं जो लम्बी अवधि के लिए होते हैं तथा जिन पर ब्याज की दर कम होती है। अनुदार ऋण अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दर व सीमित अवधि के लिए होते हैं। यह ऋण भी दो प्रकार के होते हैं** एक तो वे जो किसी विशेष कार्य के लिए दिये जाते हैं। दूसरे

Scanned with CamScanner

वे जो किसी विशेष कार्य के लिए नहीं दिये जाते हैं जिन्हें क्रमशः **प्रोजेक्ट ऋण** (Project Loans) **व गैर-प्रोजेक्ट ऋण** (Non-Project Loans) कहते हैं।

(3) **अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा ऋण**—अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भी ऋणों के रूप में विदेशी पूंजी प्रदान की जाती है। यह संस्थाएँ हैं अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन, एशियाई विकास बैंक, आदि। इन संस्थाओं द्वारा ऋण निजी व सार्वजनिक दोनों प्रकार के क्षेत्रों को दिये जाते हैं।

Scanned with CamScanner

विदेशी पूँजी का महत्व
(The Importance of Foreign Capital)

प्रो. आस्कर लेंज के अनुसार, "वर्तमान युग में, अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास का भविष्य मुख्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अर्थात् विदेशी पूँजी पर निर्भर करता है।" अल्पविकसित देशों के विषय में विदेशी पूँजी का योगदान निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण माना जाता है—

(1) **घरेलू बचतों को अनुपूरित करना**—अल्पविकसित देशों की विशिष्टता यह बताई जाती है कि वे "पूँजी दरिद्र" या "कम बचत तथा कम निवेश करने वाली" अर्थव्यवस्थाएँ हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं का न केवल पूँजी-स्टॉक न्यून होता है बल्कि पूँजी-निर्माण की चालू दर भी बहुत कम होती है। इन देशों में प्राय: सकल निवेश, सकल राष्ट्रीय आय का केवल 5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक होता है, जबकि बचत की दर 2 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत तक होती है। इन देशों में बढ़ती जनसंख्या दर के कारण निवेश का प्रतिशत कम से कम 10% होना चाहिए। घरेलू बचतें जब निवेश के माध्यम से पूँजी-निर्माण की दर बढ़ाने में असमर्थ रहती हैं तो ऐसी स्थिति में विदेशी पूँजी का आयात, पूँजीगत उपकरण और कच्चे माल की पूर्ति को बढ़ाकर इस कमी को पूरा करता है जिससे घरेलू बचतें तथा पूँजी-निर्माण की दर बढ़ने लग जाती हैं।

1 Singh, S. P., *'Economic Development and Planning'*, Hindi Edi. (1994), p. 357.

Scanned with CamScanner

(2) प्राविधिक ज्ञान की कमी को दूर करना—अल्पविकसित देश केवल 'पूँजी दरिद्र' ही नहीं बल्कि 'तकनीकी दरिद्र' भी होते हैं। यहाँ प्रशिक्षित जनशक्ति, तकनीकी प्रशिक्षित श्रम तथा परामर्श देने वाले लोगों का सर्वथा अभाव पाया जाता है जिससे इन देशों में विकास की गति बड़ी धीमी होती है। विदेशी सहायता की उपलब्धता इन देशों में न केवल पूँजी के रूप में होती है अपितु तकनीकी ज्ञान एवं परामर्श के रूप में भी होती है जिससे इन देशों की तकनीकी पिछड़ेपन की समस्या को दूर किया जा सकता है।

(3) आधारभूत संरचना के निर्माण में सहायक—अल्पविकसित देश इस स्थिति में नहीं होते कि आधारभूत तथा मूल उद्योग अपने आप शुरू करें। विदेशी पूँजी के माध्यम से ही ये इस्पात, मशीन औजारों, भारी विद्युत तथा रासायनिक आदि प्लाण्टों को स्थापित कर सकते है। फिर, एक उद्योग में विदेशी पूँजी का प्रयोग अन्य उद्योगों में लागतें घटाकर देशी उद्यम को प्रोत्साहन दे सकता है जिससे अन्य सम्बद्ध उद्योगों का श्रृंखला की तरह विस्तार हो सकता है।

विदेशी पूँजी का महत्व

1. घरेलू बचतों को अनुपूरित करना
2. प्राविधिक ज्ञान की कमी को दूर करना
3. आधारभूत संरचना के निर्माण में सहायक
4. उपरिपूँजी की कमी को दूर करना
5. खनिज पदार्थों का दोहन एवं विकास
6. सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए
7. नये क्षेत्रों के विदोहन में सहायक
8. सरकारी राजस्व में बढ़ोत्तरी
9. स्फीतिकारी दबावों में कमी
10. प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन को ठीक करना

(4) उपरिपूँजी की कमी को दूर करना—अल्पविकसित देशों में आर्थिक उपरिपूँजी का अत्यन्त अभाव होता है जो अधिक निवेश को प्रत्यक्षत: सुगम बना देता है। रेलमार्ग, सड़कें, नहरें, विद्युत परियोजनाएँ, आर्थिक विकास के लिए आवश्यक आधारिक संरचना (Infrastructure) प्रदान करती हैं परन्तु क्योंकि उनके लिए बहुत बड़े निवेशों की आवश्यकता होती है और उनकी प्रतिफल देने की अवधि भी लम्बी होती है, इसलिए ऐसे देश विदेशी पूँजी के बिना उन्हें शुरू नहीं कर सकते।

(5) खनिज पदार्थों का दोहन एवं विकास—प्राय: अल्पविकसित देशों में सह-उद्यम का अभाव होता है। यही नहीं, यहाँ साहसी किसी भी प्रकार का जोखिम नये साधनों की खोज में उठाने को तत्पर नहीं होता है। विदेशी पूँजी प्रारम्भिक अवस्था की सब जोखिमों तथा हानियों को उठा लेती है। यह नये प्राकृतिक साधनों को खोजकर उनके उचित दोहन एवं प्रयोग को बढ़ाता है और इस प्रकार देश के विकास को बढ़ावा देता है।

(6) सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए—देश की आधारिक संरचना का निर्माण, नये उद्योगों की स्थापना, नये संसाधनों का प्रयोग तथा नये क्षेत्रों का विकास, ये सब अर्थव्यवस्था के भीतर रोजगार के सुअवसर बढ़ाते हैं। दूसरे शब्दों में, पूँजी का आयात शहरी क्षेत्र में अधिक रोजगार का निर्माण करता है। इससे ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में अतिरेक श्रम का स्थानान्तरण होता है। भूमि पर जनसंख्या का दबाव घट जाता है और हो सकता है कि अदृश्य बेकारी दूर हो जाये। विदेशी पूँजी से यह सामाजिक लाभ है।

(7) नये क्षेत्रों के विदोहन में सहायक—अल्पविकसित देशों में एक तो उद्यम-वृत्ति का अभाव होता है और दूसरा, घरेलू पूँजी शर्मीली होती है। निजी उद्यम भारी जोखिम वाले उद्यमों, जैसे—प्राकृतिक साधनों और नये क्षेत्रों के विदोहन में निवेश करने के लिए तैयार नहीं होता जिससे अनेक क्षेत्र अविकसित अवस्था में पड़े रहते है। विदेशी पूँजी निवेश की पहल करती है, प्रारम्भिक अवस्था की सब जोखिमें उठाती है, **अगम्य क्षेत्रों** (Inaccessible Areas) को खोलती है, नये प्राकृतिक साधनों की खोज करती है और प्रादेशिक असन्तुलनों को दूर करती है।

(8) सरकारी राजस्व में बढ़ोत्तरी—सरकार निजी एवं विदेशी निवेशकों के लाभों पर कर एवं प्रशुल्क लगाकर अपने राजस्व में वृद्धि कर सकती है। यही नहीं, यह विदेशी निवेशकों की रॉयल्टी पर भी कर लगाकर अपनी आय में बढ़ोत्तरी कर सकती है।

(9) स्फीतिकारी दबावों में कमी—विकासशील देशों में विकास की प्रारम्भिक अवस्था में स्फीतिक दबाव अधिक रहता है और यह भारी सार्वजनिक निवेश के कारण, घरेलू वस्तुओं की माँग तथा पूर्ति के असन्तुलन का परिणाम होता है। विदेशी पूँजी की सहायता से उपलब्ध खाद्यान्नों एवं उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति, माँग के साथ सन्तुलन स्थापित कर स्फीतिक दबाव से मुक्ति दिलाता है।

(10) प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन को ठीक करना—विदेशी पूँजी भुगतान-शेष की उन कठिनाइयों को दूर करती है जिन्हें एक अल्पविकसित देश विकास की प्रक्रिया में अनुभव करता है। अल्पविकसित देशों में विकास की प्रक्रियाओं में आयात की अधिकता होती है जिससे इनका भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल बना रहता है।

Scanned with CamScanner

विदेशी पूँजी की सहायता से एक ओर घरेलू बाजार का विकास करके निर्यात को बढ़ाने में सहायता मिलती है तो दूसरी ओर विदेशी ऋणों के भुगतान को पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार विदेशी सहायता से प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन को ठीक करने में सहायता मिलती है।

विदेशी पूँजी (सहायता) के दोष या सीमाएँ
(Disadvantages or Limitations of Foreign Capital)

विदेशी पूँजी को विकासशील देशों के लिए एक दोष-रहित वरदान नहीं कहा जा सकता है। विदेशी पूँजी के जहाँ अनेक लाभ हैं, वहीं इस पर बहुत अधिक निर्भरता खतरे से खाली नहीं है। यदि विदेशी पूँजी अल्प-विकसित देशों के तीव्र आर्थिक विकास हेतु एक महत्वपूर्ण एवं मजबूत सम्बल है तो इन देशों के आर्थिक शोषण, राजनीतिक उत्पीड़न और विकास के प्रारूप को विकृत करने का श्रेय भी विदेशी पूँजी को प्राप्त है। विदेशी पूँजी के प्रमुख दोष इस प्रकार हैं—

विदेशी पूँजी (सहायता) के दोष या सीमाएँ

1. विदेशी सहायता विकास के लिए आवश्यक शर्त नहीं
2. ऋण-भार में उत्तरोत्तर वृद्धि
3. विदेशी सहायता आय-अर्जन क्षमता को नहीं सुधारती
4. विदेशी विनिमय संकटपूर्ण
5. आर्थिक शोषण
6. विकास के प्रारूप का विकृत होना
7. विदेशी सहायता निर्भरता लाती है
8. भुगतान सन्तुलन पर बुरा प्रभाव
9. घरेलू बचतों में कमी

(1) विदेशी सहायता विकास के लिए आवश्यक शर्त नहीं—**प्रो. बौर** (Bauer) के अनुसार, अल्पविकसित देशों के विकास के लिए विदेशी सहायता अनिवार्य नहीं है। उसके शब्दों में, "विदेशी सहायता गरीबी से ऊपर उठने के लिए स्पष्टतया न तो सामान्यत: आवश्यक और न ही पर्याप्त शर्त है।" यह आर्थिक विकास के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि बहुत-से नये विकसित देश प्रारम्भ में अल्पविकसित थे तथा बिना विदेशी सहायता के विकसित हुए।

(2) ऋण-भार में उत्तरोत्तर वृद्धि—विदेशी ऋणों का भार आन्तरिक ऋणों की तुलना में अधिक होता है। इसका कारण यह है कि विदेशी ऋणों का भुगतान केवल विदेशी करेंसी अथवा विदेशी विनिमय के रूप में ही करना पड़ता है। चूँकि अल्पविकसित देशों का विदेशी विनिमय-कोष पहले ही काफी कम होता है और फिर, ये देश ऋण सेवा भार (ब्याज) को वहन करने की स्थिति में भी नहीं होते। फलस्वरूप ऋण परिशोधन का बढ़ता हुआ भार इन देशों को और अधिक ऋण लेने के लिए विवश कर देता है जिससे यह देश उत्तरोत्तर ऋणग्रस्तता के विषम चक्र में फँसते चले जाते हैं।

(3) विदेशी सहायता आय-अर्जन क्षमता को नहीं सुधारती—विदेशी सहायता अल्पविकसित देशों की आय-अर्जन क्षमता को सुधारने में विफल रही है और वे विशाल वाह्य सार्वजनिक ऋणों से अब दबे हुए हैं।

(4) विदेशी विनिमय संकटपूर्ण—सहज रूप में प्राप्त होने वाली विदेशी पूँजी से देश का भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल हो जाता है। अल्पविकसित देशों का भुगतान सन्तुलन एक तो पहले ही प्रतिकूल होता है, दूसरे, उस पर ऋण सेवा भार (ब्याज) और ऋण परिशोधन भार इस भुगतान सन्तुलन पर और अधिक दबाव डालता है। परिणामस्वरूप ऋणी देश का विदेशी विनिमय संकट और भी गहरा हो जाता है।

(5) आर्थिक शोषण—भूतकाल में विदेशी पूँजी पिछड़े हुए राष्ट्रों के आर्थिक शोषण का एक प्रमुख साधन रही है। इसका जीता-जागता उदाहरण उपनिवेशवाद का वह घिनौना इतिहास है जिसके अन्तर्गत उपनिवेशीय देशों का खुलकर आर्थिक शोषण किया गया। यद्यपि पिछले दो-तीन दशकों से विदेशी पूँजी का स्वरूप काफी बदल चुका है और उसके द्वारा अब शोषण की सम्भावना भी बहुत कम है परन्तु प्रतिकूल परिस्थिति कभी भी आ सकती है।

(6) विकास के प्रारूप का विकृत होना—आज अधिकांश अल्पविकसित देश अपने तीव्र आर्थिक विकास के लिए नियोजन पद्धति को अपनाये हुए हैं। विदेशी पूँजी का स्वतन्त्र आगमन विकास की प्राथमिकताओं के क्रम को अस्त-व्यस्त कर देता है। इसका कारण यह है कि विदेशी पूँजी प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में न जाकर, लाभ-पूर्ण क्षेत्रों में जाने की अधिक प्रवृत्ति रखती है। इस प्रकार विदेशी पूँजी ऋणी देश के विकास में सहायक कम, बाधक अधिक सिद्ध होती है।

(7) विदेशी सहायता निर्भरता लाती है—विदेशी सहायता निर्भरता लाती है क्योंकि दाता बद्ध (Tied) सहायता पर बल देते हैं जिसके अनुसार प्रतियोगी विश्व कीमतों की अपेक्षा दाता वस्तुओं और सेवाओं को

Scanned with CamScanner

ऊँची लागतों पर बेचते हैं तथा ऐसी मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ अपनाने को कहते हैं जो सहायता प्राप्तकर्ता के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध होती हैं।

(8) **भुगतान सन्तुलन पर बुरा प्रभाव**—सहज रूप में प्राप्त होने वाली विदेशी पूँजी से भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता बढ़ती है। अल्पविकसित देशों द्वारा विकासात्मक आयात अधिक किये जाने के कारण, इनका भुगतान सन्तुलन पहले ही प्रतिकूल होता है। उस पर, ऋण-परिशोधन और ऋण सेवा भार इस भुगतान सन्तुलन पर और अधिक दबाव डालता है जिसके कारण विदेशी विनिमय संकट और भी गहरा हो जाता है।

(9) **घरेलू बचतों में कमी**—**ग्रिफिन** एवं **एनोस**[1] ने 35 अल्पविकसित देशों के सांख्यिकीय प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष दिया है कि विदेशी सहायता का केवल 25 प्रतिशत आयातों और निवेश में वृद्धि करता है जबकि 75 प्रतिशत उपभोग के लिए प्रयोग किया जाता है। अत: सहायता घरेलू बचतों में कमी करती है। यह घरेलू बचतों के स्थानापन्न के रूप में प्रयोग की जाती है, न कि पूरक के रूप में। दूसरी ओर, **पपानेक**[2] का आनुभविक प्रमाण यह दर्शाता है कि सहायता बचतों को प्रोत्साहित करती है जिससे प्रति डॉलर के अन्तर्प्रवाह से एक डॉलर से अधिक निवेश होता है जबकि कुछ अन्य देशों में वे बचतों को हतोत्साहित करती हैं तथा एक डॉलर की सहायता के अन्तर्प्रवाह से एक डॉलर से कम निवेश होता है।

निष्कर्ष यह है कि विदेशी पूँजी अल्पविकसित देशों की आत्म-निर्भरता के लिए एक बड़ा खतरा है। यह ऐसी दोधारी तलवार है जिससे दुश्मन का सिर तो कटता ही है, अपना सिर भी कट सकता है। अत: विदेशी पूँजी के प्रयोग हेतु अत्यन्त सावधानी की आवश्यकता होती है।

Scanned with CamScanner